Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com
ISSN:2584-105X Pg. 197 - 203

आजमगढ़ जनपद में ग्रामीण विकास की स्थिति: एक समीक्षा अध्ययन

डा० श्रीचन्द्र राजभर
पी०एच०डी० (भूगोल)
शिबली नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जनपद – आजमगढ़ (उ०प्र०)

Accepted: 22/07/2025
Published: 27/07/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.18242939*

सारांश

यह शोध-पत्र उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में ग्रामीण विकास की स्थिति का समीक्षा (review) अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, आधारभूत अवसंरचना, स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, आजीविका, तथा शासन/योजनाओं के क्रियान्वयन की समग्र तस्वीर बनाना है। पद्धति के रूप में द्वितीयक आँकड़ों (secondary data) और उपलब्ध साहित्य का विषय-वस्तु आधारित विश्लेषण अपनाया गया है। प्रमुख स्रोतों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का जिला प्रोफाइल, NITI Aayog/IFPRI का जिला पोषण प्रोफाइल (NFHS 4 बनाम NFHS 5 के तुलनात्मक संकेतक), SECC 2011 की ग्रामीण घरेलू-आधारित स्थिति, MSME मंत्रालय का जिला औद्योगिक प्रोफाइल, तथा क्षेत्रीय/विषयगत शोध-पत्र शामिल हैं। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ एक प्रमुखतः ग्रामीण जनपद है जहाँ कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शहरीकरण का स्तर सीमित है (NHM, 2016)। ग्रामीण विकास के संदर्भ में जनपद की बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वच्छता/खुले में शौच से जुड़े संकेतकों में सुधार, तथा स्वास्थ्य सेवाओं की संस्थागत संरचना का विस्तार दिखता है; परंतु दूसरी ओर बाल कुपोषण, एनीमिया, रोजगार की अनिश्चितता, कृषि पर अधिक निर्भरता और श्रम पलायन जैसी चुनौतियाँ अब भी महत्वपूर्ण हैं (Singh et al., 2022; Singh, 2023)। अवसंरचना पक्ष में ग्रामीण सड़कों/कनेक्टिविटी में पहले से मौजूद नेटवर्क के साथ हाल के वर्षों में एक्सप्रेसवे-आधारित कनेक्टिविटी (जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ के सालारपुर बिंदु तक जुड़ाव) ने क्षेत्रीय बाजार पहुँच को नया आयाम दिया है (UPEIDA, 2025)। अध्ययन का निष्कर्ष है कि आजमगढ़ में ग्रामीण विकास की प्रगति "आंशिक परंतु असमान" (uneven) रही है; इसलिए कृषि आधारित मूल्य संवर्धन, गैर कृषि रोजगार, पोषण स्वास्थ्य अभिसरण, महिला सशक्तीकरण, और पंचायत-स्तरीय डेटा आधारित योजना को प्राथमिकता देकर विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।[1]

मुख्य शब्द: *ग्रामीण विकास, आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कृषि एवं आजीविका, स्वास्थ्य पोषण, SECC, अवसंरचना, पलायन, पंचायत नियोजन*

1. भूमिका

ग्रामीण विकास का आशय केवल सड़क, बिजली या आवास तक सीमित नहीं है; यह आय-सुरक्षा, अवसरों तक पहुँच, मानव पूंजी (शिक्षा-स्वास्थ्य), सामाजिक न्याय, संस्थागत क्षमता, और स्थानीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से जुड़ा बहुआयामी (multi-dimensional) परिवर्तन है। रॉबर्ट चेम्बर्स ने ग्रामीण विकास को "अंतिम व्यक्ति" (the last) की ओर प्राथमिकता देने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा—जहाँ नीति और कार्यक्रमों का केंद्र गरीब, वंचित और छोटे किसान/भूमिहीन वर्ग होते हैं (Chambers, 1983)। अमर्त्य सेन ने विकास को "क्षमताओं/स्वतंत्रताओं के विस्तार" (expansion of capabilities) के रूप में परिभाषित किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा और विकल्प—सब विकास के मानक हैं (Sen, 1999)।

उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ऐतिहासिक रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व, छोटे जोत आकार, कृषि पर निर्भरता, सीमित औद्योगिकीकरण, तथा श्रम पलायन जैसी विशेषताओं के लिए चर्चित रहा है। आजमगढ़ इसी सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र का प्रमुख जनपद है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास की समीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन (implementation) अक्सर ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर होता है और परिणाम भी वहीं दिखाई देते हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध-पत्र आजमगढ़ जनपद में ग्रामीण विकास की स्थिति का एक समग्र, प्रमाण-आधारित (evidence-based) समीक्षा अध्ययन प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय: आजमगढ़ जनपद (Study Area Profile)

द्वितीयक स्रोतों के अनुसार आजमगढ़ जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 4054 वर्ग किमी है और यह मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर तथा अम्बेडकरनगर आदि जिलों से घिरा हुआ है। प्रशासनिक संरचना में (स्रोत वर्षानुसार) तहसील/उप-जिला, 22 विकासखंड, ग्राम पंचायतें और हजारों गाँव शामिल हैं (Ministry of MSME, n.d.; NHM, 2016)।

2.1 जनसांख्यिकीय विशेषताएँ और ग्रामीणता का स्तर

NHM जिला प्रोफाइल (Census 2011 आधारित) के अनुसार आजमगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग 0.46 करोड़ है और ग्रामीण जनसंख्या 42.20 लाख दर्ज है। शहरी आबादी का अनुपात कम है—जिला प्रोफाइल में शहरी जनसंख्या लगभग 3.93 लाख तथा कुल का लगभग 8.5% बताया गया है (NHM, 2016)। यह तथ्य आजमगढ़ को "मुख्यतः ग्रामीण" (predominantly rural) जनपद सिद्ध करता है, जहाँ विकास की दिशा और गति को समझने के लिए ग्रामीण संकेतकों पर विशेष फोकस आवश्यक हो जाता है।

2.2 सामाजिक संरचना (लिंगानुपात, साक्षरता)

जिला प्रोफाइल के अनुसार आजमगढ़ में लिंगानुपात 1019 तथा बाल लिंगानुपात 919 है। कुल साक्षरता 70.9%, पुरुष साक्षरता 81.3% और महिला साक्षरता 60.9% दर्ज है (NHM, 2016)। ये संकेतक बताते हैं कि एक ओर लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से बेहतर है, दूसरी ओर महिला शिक्षा का अंतर (gender gap) ग्रामीण विकास की गुणवत्ता/समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहता है।

3. उद्देश्य (Objectives)

इस समीक्षा अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

1. आजमगढ़ जनपद में ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति को जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर समझना।
2. कृषि, आजीविका, अवसंरचना, स्वास्थ्य-पोषण और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों/कमियों की पहचान करना।
3. SECC तथा अन्य द्वितीयक स्रोतों के आधार पर गरीबी/असुरक्षा के संकेतकों का विश्लेषण करना।
4. शासन, संस्थागत ढाँचे और विकास कार्यक्रमों की दिशा में प्रमुख चुनौतियाँ तथा अवसरों का मूल्यांकन करना।
5. जिले के संदर्भ में नीति-स्तर और क्रियान्वयन-स्तर पर व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध विधि (Methodology): "समीक्षा अध्ययन" का ढाँचा

यह अध्ययन **वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक** (descriptive-analytical) प्रकृति का है और इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण के बजाय **द्वितीयक आँकड़ों एवं साहित्य** की समीक्षा की गई है।

4.1 डेटा स्रोत (Secondary Sources)

इस अध्ययन में निम्न प्रमुख स्रोतों का उपयोग किया गया—

- **NHM जिला प्रोफाइल (2016-17)**: जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य ढाँचा, चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतक। (NHM, 2016)
- **जिला पोषण प्रोफाइल (DNP)**: NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के

तुलनात्मक पोषण-स्वास्थ्य संकेतक। (Singh et al., 2022)

- **SECC-2011 (ग्रामीण)**: घरेलू-स्तर पर आय-स्लैब, भूमि-स्थिति, परिसंपत्ति/फोन-स्वामित्व जैसे संकेतक। (Ministry of Rural Development, 2011)
- **MSME जिला औद्योगिक प्रोफाइल**: जिला संरचना, सड़क/संचार/शिक्षा सुविधाएँ, औद्योगिक क्लस्टर संकेत। (Ministry of MSME, n.d.)
- **क्षेत्रीय/विषयगत शोध-पत्र**: कृषि-भूमि उपयोग और ग्रामीण विकास के पक्ष (Rai & Singh, 2018; Tiwari & Gautam, 2021) तथा पलायन-आजीविका (Singh, 2023)।
- **UPEIDA**: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की विशेषताएँ व आजमगढ़ से जुड़ाव। (UPEIDA, 2025)

4.2 विश्लेषण पद्धति

डेटा को विषयानुसार (thematic) वर्गीकृत कर—

- **रुझान विश्लेषण** (NFHS-4 बनाम NFHS-5)
- **संकेतक-आधारित व्याख्या** (SECC के गरीबी/असुरक्षा संकेतक)
- **क्षेत्रीय-अवसंरचना व्याख्या** (सड़क/कनेक्टिविटी/सेवाएँ)
- किया गया।

4.3 सीमाएँ (Limitations)

1. कई स्रोतों के आँकड़े अलग-अलग वर्षों से संबंधित हैं (जैसे SECC-2011, Census-2011; स्वास्थ्य/पोषण के लिए NFHS-4/5)। अतः निष्कर्ष "वर्तमान" की जगह **"हालिया उपलब्ध प्रमाण"** (best available evidence) पर आधारित हैं।
2. ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर की सूक्ष्म विविधताएँ इस समीक्षा में सीमित रूप से ही पकड़ी जा सकीं।
3. कुछ योजनागत संकेतकों (जैसे PMAY-G, JJM की अद्यतन प्रगति) के लिए सर्वसुलभ जिला-वार आँकड़ों का एकीकृत उपयोग इस लेख में सीमित रहा।

5. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

आजमगढ़ के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य मोटे तौर पर तीन धाराओं में दिखता है—

5.1 ग्रामीण विकास की वैचारिक पृष्ठभूमि

क्लासिकल साहित्य में चेम्बर्स (1983) ग्रामीण गरीबी, असमानता, और संस्थागत बाधाओं को केंद्र में रखकर विकास की प्रक्रिया को "नीचे से ऊपर" (bottom-up) बनाने पर जोर देते हैं। सेन (1999) विकास को मानव स्वतंत्रता/क्षमताओं के विस्तार से जोड़ते हैं। इन दृष्टियों से आजमगढ़ जैसे जनपद में केवल अवसंरचना नहीं, बल्कि **शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार अवसरों** का विस्तार विकास का असली मानक बनता है।

5.2 आजमगढ़ में कृषि-भूमि उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

स्थानीय/क्षेत्रीय अध्ययनों में कृषि विकास के संदर्भ में भूमि उपयोग, सिंचाई, जनसंख्या दबाव तथा फसल-प्रतिरूप जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। Rai और Singh (2018) ने भूमि उपयोग और कृषि विकास के संदर्भ में आजमगढ़ पर केंद्रित अध्ययन प्रस्तुत किया। इसी तरह Tiwari और Gautam (2021) ने फसल भूमि उपयोग, जनसंख्या क्रियाशीलता तथा ग्रामीण विकास के सामाजिक-आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन किया। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जनपद में कृषि प्रधानता बनी हुई है, परंतु संसाधन-सीमाएँ और जनसंख्या दबाव विकास की दिशा को प्रभावित करते हैं।

5.3 पलायन, रोजगार और सामाजिक संरचना

आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में माना जाता है जहाँ **पुरुष श्रम पलायन** एक महत्वपूर्ण आजीविका रणनीति बन चुका है। Ruchi Singh (2023) का अध्ययन आजमगढ़ के एक गाँव में प्राथमिक सर्वे के आधार पर दिखाता है कि आर्थिक अवसरों की कमी और श्रम बाजार संरचना (जैसे जाति-आधारित अवसर) पलायन पैटर्न से जुड़ते हैं। इस साहित्य का नीति-संदेश यह है कि **स्थानीय गैर-कृषि रोजगार** और **MNREGA/कौशल विकास** जैसे कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन ग्रामीण असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है (Singh, 2023)।

6. निष्कर्ष

6.1 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका संरचना

आजमगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः **कृषि एवं उससे जुड़े अनौपचारिक श्रम** पर टिका है। SECC-2011 के ग्रामीण घरेलू आँकड़ों से जिले में आर्थिक भेद्यता (vulnerability) का संकेत मिलता है। जिला-स्तर पर कुल **615,199 ग्रामीण परिवारों** में से **61.99%** परिवारों में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की मासिक आय **₹5000 से कम** दर्ज है। साथ ही **8.61%** परिवार "भूमिहीन" हैं और उनकी आय का मुख्य स्रोत **दैनिक/मैनुअल कैजुअल लेबर** बताया गया है (Ministry of Rural Development, 2011)। यह स्थिति दर्शाती है कि ग्रामीण विकास की प्राथमिकता केवल उत्पादन बढ़ाने

तक सीमित नहीं हो सकती; उसे **आय-स्थिरता, जोखिम-प्रबंधन, और वैकल्पिक रोजगार** सृजन की दिशा में भी जाना होगा।

SECC संकेतकों में परिसंपत्ति-स्वामित्व की स्थिति भी मिश्रित तस्वीर देती है। जिला-कुल में लगभग **93.14%** परिवारों के पास "केवल मोबाइल" होने का संकेत मिलता है, जबकि "कोई फोन नहीं" वाले परिवार भी मौजूद हैं; मोटराइज्ड दो/तीन/चार पहिया वाहन वाले परिवारों का अनुपात लगभग **40.6%** बताया गया है (Ministry of Rural Development, 2011)। इन संकेतकों को यदि "डिजिटल पहुँच" और "आय-क्षमता" के संकेतक के रूप में देखें, तो यह समझ आता है कि डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ी है, पर **गरीबी/कम आय** की समस्या व्यापक रूप में बनी हुई है।

6.2 कृषि, भूमि उपयोग और ग्रामीण विकास

कृषि आजमगढ़ की ग्रामीण आजीविका का केंद्रीय क्षेत्र है। स्थानीय शोध-पत्रों में फसल-प्रतिरूप (जैसे गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि), भूमि उपयोग और जनसंख्या दबाव का संबंध रेखांकित किया गया है (Rai & Singh, 2018; Tiwari & Gautam, 2021)। ऐसे अध्ययनों से नीति-स्तर पर यह संकेत मिलता है कि कृषि विकास को केवल उत्पादन-वृद्धि नहीं, बल्कि **जल-प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, इनपुट लागत, बाजार पहुँच, और जोखिम (बाढ़/सूखा/कीट)** के साथ समेकित रूप में देखना होगा।

MSME जिला औद्योगिक प्रोफाइल में भूमि उपयोग और कृषि से जुड़ी बुनियादी सूचनाएँ (जैसे कुल क्षेत्र, वन क्षेत्र का सीमित आकार, कृषि-संबंधित ढाँचा) भी मिलती हैं, जो बताती हैं कि जिले में **वन आवरण बहुत कम** और कृषि भूमि का दबाव अधिक है (Ministry of MSME, n.d.)। ऐसे परिदृश्य में "टिकाऊ ग्रामीण विकास" के लिए **जल-संरक्षण, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, और कृषि-आधारित विविधीकरण** (बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, मधुमक्खी-पालन आदि) की भूमिका बढ़ जाती है।

6.3 अवसंरचना (Infrastructure): सड़क, संचार, और बाजार पहुँच

ग्रामीण विकास में सड़क, परिवहन, संचार और बाजार-कनेक्टिविटी की भूमिका निर्णायक होती है—क्योंकि यह **इनपुट-आउटपुट बाजार, स्वास्थ्य-शिक्षा सेवाएँ, और रोजगार गतिशीलता** को प्रभावित करती है। MSME जिला प्रोफाइल के अनुसार (2010-11 संदर्भ) जिले में **राज्य राजमार्ग ~252 किमी**, **मुख्य जिला मार्ग ~237 किमी**, और **अन्य जिला/ग्रामीण सड़कें ~4227 किमी** दर्ज की गईं (Ministry of MSME, n.d.)। इसी स्रोत में डाकघर (लगभग 406), मोबाइल कनेक्शन आदि के संकेतक भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि सेवा-नेटवर्क मौजूद है पर उसकी गुणवत्ता/समयबद्धता ग्रामीण जीवन को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकती है।

हाल के वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे-आधारित कनेक्टिविटी का नया चरण दिखता है। UPEIDA के अनुसार **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे** की कुल लंबाई **91.352 किमी** है, परियोजना लागत **₹7283.28 करोड़** (भूमि लागत सहित) बताई गई है, और इसका **एंड-पॉइंट सालारपुर (जनपद आजमगढ़)** पर **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे** से जुड़ता है; UPEIDA के अनुसार इसका उद्घाटन **20.06.2025** को संपन्न हुआ (UPEIDA, 2025)। इस प्रकार की परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में "कनेक्टिविटी-लाभ" (connectivity dividend) पैदा कर सकती हैं—जैसे उत्पादों की बाजार पहुँच, परिवहन समय में कमी, तथा सेवा/औद्योगिक गतिविधि की संभावना—परंतु वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि **फीडर रोड, ग्रामीण हाट-बाजार, लॉजिस्टिक्स, और स्थानीय उद्यमिता** को कितनी मजबूती मिलती है।

6.4 स्वास्थ्य ढाँचा और सेवा-उपलब्धता (Health System)

ग्रामीण विकास का "मानव विकास" पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से सीधे जुड़ा है। NHM जिला प्रोफाइल के अनुसार आजमगढ़ में **जिला अस्पताल 2**, **CHC 19**, **PHC 77**, तथा **उप-केंद्र 493** दर्ज हैं (RHS 2014 संदर्भ सहित) (NHM, 2016)। यह ढाँचा आकार में बड़ा लगता है, पर प्रोफाइल यह भी इंगित करता है कि **77 PHC में से केवल 22 PHC 24×7** कार्यरत थे और FRU जैसी उन्नत सेवाओं की उपलब्धता सीमित थी (NHM, 2016)। यह तथ्य ग्रामीण स्वास्थ्य-सेवा में "संरचना बनाम कार्यक्षमता" (infrastructure vs functionality) की चुनौती को सामने लाता है।

6.5 पोषण और स्वास्थ्य परिणाम (Nutrition Outcomes): NFHS-4 से NFHS-5 तक

NITI Aayog/IFPRI के जिला पोषण प्रोफाइल में NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के तुलनात्मक परिणाम दिए गए हैं। बच्चों (0-5 वर्ष) में **Stunting** लगभग **40% से घटकर 33%**, **Wasting 17% से 14%**, **Underweight 33% से 28%** तथा बच्चों में **एनीमिया 62% से 59%** जैसी दिशा दिखाई देती है (Singh et al., 2022)। यह सुधार सकारात्मक है, पर स्तर अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टि से "उच्च" श्रेणी में माना जा सकता है—अर्थात पोषण-स्थिति ग्रामीण विकास की बड़ी बाधा बनी रहती है।

महिलाओं के संदर्भ में भी DNP संकेतक महत्वपूर्ण हैं। प्रोफाइल के अनुसार महिलाओं में **Underweight** का अनुपात **27% से 22%** की ओर घटता दिखता है, जबकि **Overweight/Obesity 16% से 22%** की ओर बढ़ता

दिखता है; साथ ही **हाइपरटेंशन 12% से 19%** तक बढ़ने का संकेत मिलता है (Singh et al., 2022)। यह ग्रामीण-अर्धशहरी संक्रमण (nutrition transition) जैसी स्थिति का संकेत है, जहाँ एक तरफ कुपोषण/एनीमिया, दूसरी तरफ NCD जोखिम (उच्च रक्तचाप, मोटापा) उभरते हैं।

6.6 स्वच्छता, पानी और सामाजिक निर्धारक (Underlying Determinants)

DNP का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह पोषण को केवल "भोजन" नहीं, बल्कि **स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा उपयोग, और सामाजिक सुरक्षा** जैसे निर्धारकों से जोड़ता है। आजमगढ़ के लिए उपलब्ध संकेतकों में घरेलू स्वच्छता से जुड़े सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—उदाहरणार्थ **improved sanitation** का अनुपात **26% से 73%** की ओर बढ़ता दिखता है (NFHS-4 से NFHS-5) (Singh et al., 2022)। इस तरह का परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (IEC/BCC) के प्रभाव का संकेत दे सकता है—हालाँकि "उपयोग" और "स्थायित्व" (sustained usage) की गुणवत्ता अलग विश्लेषण मांगती है।

महिला शिक्षा भी एक संरचनात्मक निर्धारक है। DNP में "10+ वर्षों की शिक्षा" वाली महिलाओं का अनुपात **47% से 53%** की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है (Singh et al., 2022)। यह ग्रामीण विकास के लिए सकारात्मक है, क्योंकि महिला शिक्षा का संबंध बाल-स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन और आय-निर्णयों से जुड़ता है।

6.7 शिक्षा, मानव पूंजी और अवसर संरचना

शिक्षा ग्रामीण विकास में दीर्घकालिक बदलाव का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। MSME जिला प्रोफाइल (2010-11 संदर्भ) के अनुसार जिले में **प्राथमिक विद्यालय ~3071**, **मिडिल स्कूल ~1302**, **सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी ~472**, तथा **कॉलेज ~20** का उल्लेख मिलता है (Ministry of MSME, n.d.)। वहीं NHM प्रोफाइल में साक्षरता और महिला-पुरुष अंतर का संकेत मिलता है (NHM, 2016)। इन दोनों को साथ रखकर देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा का नेटवर्क पर्याप्त फैलाव वाला है, पर **गुणवत्ता, उपस्थिति, सीखने के परिणाम (learning outcomes), और लड़कियों की निरंतरता** (retention) जैसे आयाम ग्रामीण विकास के लिए निर्णायक बने रहते हैं।

6.8 ग्रामीण गरीबी/असुरक्षा का बहुआयामी स्वरूप

SECC-2011 का लाभ यह है कि वह गरीबी को केवल "BPL" के रूप में नहीं, बल्कि आय-स्रोत, भूमि-स्थिति, नौकरी-प्रकार, परिसंपत्ति और सेवाओं की पहुँच जैसे संकेतकों से दिखाता है। आजमगढ़ में **कम आय (₹5000 से कम)** का उच्च अनुपात, साथ ही **भूमिहीन दैनिक श्रम** वाले परिवारों का उल्लेख, ग्रामीण असुरक्षा की जड़ों को सामने लाता है (Ministry of Rural Development, 2011)।

इस परिदृश्य में ग्रामीण विकास की नीति-दृष्टि को "रिलीफ-ओरिएंटेड" (केवल सहायता/सब्सिडी) से आगे बढ़कर "रेज़िलिएंस-ओरिएंटेड" (resilience) बनना होगा—अर्थात कौशल, क्रेडिट, उत्पादक परिसंपत्ति, महिला SHG, सामाजिक सुरक्षा, और स्थानीय रोजगार—इन सबका संयोजन।

6.9 पलायन का विकास पर प्रभाव: अवसर भी, चुनौती भी

Ruchi Singh (2023) का अध्ययन आजमगढ़ को उच्च पुरुष पलायन वाले जिले के रूप में रेखांकित करता है और दिखाता है कि ग्रामीण परिवारों के लिए पलायन एक **आर्थिक रणनीति** है, पर अवसर-संरचना जाति/शिक्षा/कौशल से भी प्रभावित होती है (Singh, 2023)। पलायन से रेमिटेंस (remittances) द्वारा आय-सहारा मिल सकता है, पर इसके साथ **गाँव में श्रम की कमी/अस्थिरता, महिलाओं पर कार्य-भार, बच्चों की देखरेख, तथा सामाजिक-भावनात्मक लागत** भी जुड़ती है। इसलिए ग्रामीण विकास का लक्ष्य "पलायन रोकना" नहीं, बल्कि "विकल्प बढ़ाना" होना चाहिए—ताकि पलायन मजबूरी न रहे, बल्कि विकल्पों में से एक निर्णय बने।

7. शासन और संस्थागत पक्ष (Governance & Institutions)

ग्रामीण विकास का क्रियान्वयन पंचायत-स्तर पर निर्भर करता है—विशेषकर योजना चयन, लाभार्थी पहचान, सामाजिक लेखा-जोखा, और सामुदायिक भागीदारी में। MSME प्रोफाइल में ग्राम पंचायतों/गाँवों की संख्या और प्रशासनिक ढाँचे का उल्लेख मिलता है (Ministry of MSME, n.d.)। NHM प्रोफाइल में VHSNC जैसी सामुदायिक संस्थाओं के गठन की स्थिति (जैसे 1848 गाँवों में 1516 VHSNC) का उल्लेख भी मिलता है, जो स्वास्थ्य-पोषण के स्थानीय मंचों की भूमिका दिखाता है (NHM, 2016)।

ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाने के लिए शासन में तीन बातें निर्णायक हैं—

1. **अभिसरण (convergence):** स्वास्थ्य-पोषण-जल-स्वच्छता-आजीविका योजनाओं का एक साथ काम करना।

2. **डेटा-आधारित सूक्ष्म नियोजन:** ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर समस्या-मानचित्रण (problem mapping) और लक्ष्य निर्धारण।
3. **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता:** सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण, और समुदाय की निगरानी।

8. प्रमुख चुनौतियाँ

स्रोत-आधारित समीक्षा के आधार पर आजमगढ़ के ग्रामीण विकास में निम्न चुनौतियाँ प्रमुख हैं—

1. **कम आय और रोजगार अस्थिरता:** SECC के अनुसार कम आय-वर्ग की व्यापकता और दैनिक श्रम पर निर्भरता। (Ministry of Rural Development, 2011)
2. **कृषि पर उच्च निर्भरता व संसाधन दबाव:** भूमि-उपयोग/जनसंख्या दबाव का संबंध (Rai & Singh, 2018; Tiwari & Gautam, 2021)।
3. **पोषण-स्वास्थ्य का दोहरा बोझ:** बच्चों में स्टंटिंग/एनीमिया का उच्च स्तर तथा महिलाओं में NCD जोखिम बढ़ना। (Singh et al., 2022)
4. **स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता:** 24×7 सेवाओं और FRU जैसी सुविधाओं की सीमाएँ। (NHM, 2016)
5. **मानव पूंजी अंतर:** महिला-पुरुष साक्षरता अंतर और महिला शिक्षा की गुणवत्ता/निरंतरता। (NHM, 2016; Singh et al., 2022)
6. **पलायन-आधारित आजीविका निर्भरता:** स्थानीय गैर-कृषि अवसरों की कमी का संकेत। (Singh, 2023)
7. **अवसंरचना का असमान लाभ:** एक्सप्रेसवे जैसी मेगा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लाभ तभी व्यापक होंगे जब ग्रामीण फीडर-कनेक्टिविटी, बाजार/लॉजिस्टिक्स और स्थानीय उद्यमों को संगठित समर्थन मिले। (UPEIDA, 2025)

9. नीति एवं कार्यनीति सुझाव

आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

9.1 कृषि-आधारित मूल्य संवर्धन और विविधीकरण

- ब्लॉक-वार **FPO/किसान उत्पादक संगठन**, भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण (pulses, oilseeds, dairy, vegetables) और बाजार-लिंक को बढ़ावा।
- मृदा-स्वास्थ्य, जल-संरक्षण और सूक्ष्म-सिंचाई पर जोर; जोखिम-प्रबंधन हेतु मौसम-आधारित सलाह/बीमा जागरूकता।
- कृषि-आधारित रोजगार के साथ **गैर-कृषि ग्रामीण उद्यम** (कुटीर उद्योग, सेवा उद्यम) का विस्तार—जिला औद्योगिक प्रोफाइल द्वारा चिन्हित क्लस्टर-संभावनाओं (जैसे शिल्प/रस्सी/मिट्टी-आधारित कार्य) को "लाइवलीहुड क्लस्टर" के रूप में विकसित करना। (Ministry of MSME, n.d.)

9.2 रोजगार और कौशल

- ग्रामीण युवाओं के लिए मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण (स्किलिंग) को स्थानीय अर्थव्यवस्था (निर्माण, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर सेवाएँ, एग्रो-प्रोसेसिंग) से जोड़ना।
- पलायन-प्रधान क्षेत्रों में "वर्क-नियर-होम" मॉडल: स्थानीय उद्योग/सेवा इकाइयों को क्रेडिट-मार्केट-मेंटोरिंग के साथ बढ़ावा (Singh, 2023)।

9.3 स्वास्थ्य-पोषण-स्वच्छता का अभिसरण

- DNP संकेतकों के आधार पर **हाई-बर्डन ब्लॉक/ग्राम पंचायतों** की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप: गर्भावस्था ANC, IFA अनुपालन, शिशु-पूरक आहार (IYCF), एनीमिया नियंत्रण। (Singh et al., 2022)
- NHM प्रोफाइल में दिखी कार्यक्षमता चुनौतियों (24×7 PHC, FRU) को ध्यान में रखकर मानव संसाधन, रेफरल और आपात सेवाओं की सुदृढ़ता। (NHM, 2016)
- स्वच्छता उपलब्धि को **सस्टेनेबल उपयोग**, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन के अगले चरण से जोड़ना।

9.4 महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा

- महिला शिक्षा निरंतरता (secondary level completion), SHG-आधारित उद्यम और वित्तीय समावेशन को केंद्र में रखना।
- SECC में दिख रही कम आय/भूमिहीनता के संदर्भ में लक्षित सामाजिक सुरक्षा: राशन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और कौशल-समर्थित रोजगार। (Ministry of Rural Development, 2011)

9.5 कनेक्टिविटी लाभ का "स्थानीयकरण"

- एक्सप्रेसवे-आधारित कनेक्टिविटी (जैसे सालारपुर बिंदु) के आसपास **ग्रामीण हाट-बाजार अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिक्स हब/कलेक्शन सेंटर, और फीडर रोड** सुधार ताकि लाभ केवल ट्रांजिट तक सीमित न रहे। (UPEIDA, 2025)

10. निष्कर्ष

आजमगढ़ जनपद का ग्रामीण विकास परिदृश्य कई स्तरों पर प्रगति और चुनौतियों का सम्मिलित रूप है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि जिला अत्यधिक ग्रामीण है, जहाँ शिक्षा-स्वास्थ्य ढाँचा मौजूद होने के बावजूद कार्यात्मक गुणवत्ता, कुपोषण-एनीमिया, और कम आय/रोजगार अस्थिरता जैसी बाधाएँ बनी हुई हैं। NFHS-4 से NFHS-5 के बीच कुछ सुधार (विशेषकर स्वच्छता और कुछ पोषण संकेतकों में) उत्साहजनक है, लेकिन बच्चों में स्टंटिंग और एनीमिया जैसे मुद्दे अभी भी नीति-प्राथमिकता की माँग करते हैं (Singh et al., 2022)। SECC-2011 संकेतक ग्रामीण असुरक्षा की गहराई दिखाते हैं—जो यह इंगित करता है कि विकास को "योजना-आधारित लाभ" से आगे बढ़कर स्थायी आजीविका और मानव पूंजी पर केंद्रित करना होगा (Ministry of Rural Development, 2011)।

साथ ही, कनेक्टिविटी में हालिया परिवर्तन (जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ से जुड़ना) क्षेत्रीय अवसरों को बढ़ा सकता है, बशर्ते इसे स्थानीय उत्पादन-प्रणालियों, बाजार-संस्थानों और ग्रामीण उद्यमिता के साथ जोड़ा जाए (UPEIDA, 2025)। समग्र रूप से, आजमगढ़ में ग्रामीण विकास को अगले चरण में ले जाने के लिए कृषि-आधारित मूल्य संवर्धन, गैर-कृषि रोजगार, पोषण-स्वास्थ्य अभिसरण, महिला सशक्तीकरण, और पंचायत-स्तरीय डेटा-आधारित सूक्ष्म नियोजन सर्वाधिक निर्णायक रणनीतियाँ होंगी।

संदर्भ

- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India. (n.d.). *District industrial profile of Azamgarh district* (Prepared by Br. MSME-DI, Varanasi). Retrieved January 14, 2026, from https://dcmsme.gov.in/old/dips/DIP%20Azamgarh%202209x.pdf
- Ministry of Rural Development, Government of India. (2011). *Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011: All households summary (Rural) — District Azamgarh, Uttar Pradesh*. Retrieved January 14, 2026, from https://secc.dord.gov.in/getAllHhdSummaryDistrictReport.htm/09/60
- National Health Mission, Department of Health & Family Welfare, Uttar Pradesh. (2016). *District profile: Azamgarh (2016–17)*. Retrieved January 14, 2026, from https://upnrhm.gov.in/assets/site-files/dhap/districts/Azamgarh/Azamgarh__4_.pdf
- Rai, A., & Singh, S. (2018). कृषि विकास के अन्तर्गत भूमि उपयोग: आजमगढ़ जनपद का प्रतीक अध्ययन. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 4(7), 1438–1444. https://ijsrst.com/paper/9654.pdf
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Singh, R. (2023). Caste and migration: Insights from study of migrant men from rural Uttar Pradesh. *Migration and Diversity*, 2(2), 137–148. doi:10.33182/md.v2i2.2863
- Singh, N., Nguyen, P. H., Jangid, M., Singh, S. K., Sarwal, R., Bhatia, N., Johnston, R., Joe, W., & Menon, P. (2022). *District nutrition profile: Azamgarh, Uttar Pradesh*. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Retrieved January 14, 2026, from https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-07/Azamgarh-Uttar%20Pradesh.pdf
- Tiwari, A., & Gautam, A. K. (2021). जनपद आजमगढ़ में फसल भूमि उपयोग एवं जनसंख्या क्रियाशीलता का प्रतिरूप तथा ग्रामीण विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 9(6). https://ijcrt.org/papers/IJCRT2106807.pdf
- Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA). (2025). *Gorakhpur link expressway (updated status & salient features)*. Government of Uttar Pradesh. Retrieved January 14, 2026, from https://upeida.up.gov.in/en/page/gorakhpur-link-expressway

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****